झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
सिविल विधिक याचिका संख्या 692/2023

मंजूर मियां उर्फ मो. मंजूर आलम,उम्र 62 वर्ष, पिता स्वर्गीय सफीर मियां

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. आहदिल मियां
2. अख्तर अली
3. मो. मुख्तार
4. मो. जब्बार
5. अमरुल खातून
6. सकीना खातून
7. हसीना खातून
8. मणिरा खातून
9. भिकारी मियां

.... उत्तरदाता/प्रतिवादी

कोरम: माननिय न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिएः श्री पी. के. मुखोपाध्याय, अधिवक्ता
श्री एस. के. मूर्ति, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिए : श्री भैया वी. कुमार, अधिवक्ता

05 दिनांक **12.01.2024**

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह याचिका अतिरिक्त मुन्सिफ-XX, गिरिडीह ने 1999 के मूल वाद संख्या 167 द्वारा पारित दिनांक 26.04.2023 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत और जिसके तहत, शिकायत में संशोधन की मांग करने वाली सी.पी.सी. के आदेश VI नियम 17 के तहत दायर संशोधन याचिका को अनुमति दी गई है।

2. याचिका में की गई दलीलों के अनुसार मामले का संक्षिप्त तथ्य, जिसे अंकित करने की आवश्यकता है, निम्नलिखित है:-

3. याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता मूल मुकदमा संख्या 167/1999 का एक प्रतिवादी है और नोटिस प्राप्त होने पर इस मामले में उपस्थित हुआ और अन्य प्रतिवादियों के साथ मिलकर एक लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादियों के पास मुकदमे की संपत्ति पर अधिकार, शीर्षक, हित और कब्जा है और वादी को उक्त भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वादी जाली दस्तावेजों के आधार पर भूमि का दावा कर रहे हैं और इसलिए, प्रतिवादियों ने मुकदमे को खारिज करने की प्रार्थना की है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान मुकदमा समय सीमा के कानून और प्रतिकूल कब्जे द्वारा बाधित है और यह मुकदमा विशेष राहत अधिनियम की धाराएँ 34 और 42 के तहत भी बाधित है और राज्य भी वर्तमान मुकदमे में आवश्यक पार्टी है।

4. मुकदमे की संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपये से कम नहीं है और इस प्रकार, निचली अदालत के पास वर्तमान मुकदमे को सुनवाई करने के लिए कोई आर्थिक अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वादियों ने बहुत चतुराई से केवल अदालत शुल्क बचाने के उद्देश्य से मुकदमे की भूमि को अनुसूची 'सी' और 'डी' में दिखाया है, लेकिन यदि याचिका की संपूर्ण सामग्री का अवलोकन किया जाए, तो यह स्पष्ट है कि वादी अनुसूची 'ए' की भूमि, अर्थात् 8.40 एकड़ क्षेत्र के लिए और अनुसूची 'बी' की भूमि के लिए 2 एकड़ क्षेत्र के लिए घोषणा प्राप्त करना चाहते हैं। प्रतिवादियों की भूमि, 9.65 एकड़ क्षेत्र, जो अहलि मियाँ के पुत्रों की निपटाई गई भूमि है और सिज़मान मियाँ के पुत्रों की निपटाई गई भूमि भी है, यह भूदान पत्र के आधार पर है, जो वर्ष 1956 में बनाया गया था। अहलि मियाँ के पुत्रों को भूदान पत्र से 3.25 एकड़ भूमि मिली और सिज़मान मियाँ के पुत्रों को भूदान यज्ञ समिति से 6.40 एकड़ भूमि मिली और दोनों भूमि एक विशेष सीमा के भीतर एक ब्लॉक में मिल गईं और उन पर संयुक्त कब्जा हो गया। निपटान के बाद, प्रतिवादियों ने इसे लगभग 36 धान खेतों और 7 तंद भूमि के टोपरा में विभाजित किया और उक्त तंद भूमि पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया में है। उक्त धान खेतों को दो श्रेणियों में धान के खेतों में परिवर्तित किया गया है और इसे सर्वेक्षण जानने वाले आयुक्त की नियुक्ति द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

5. आगे का मामला यह है कि वर्तमान मुकदमा वर्ष 1999 में दायर किया गया था और 21 वर्षों के बाद वादियों ने 17.02.2020 को सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत याचिका दायर की, जिसमें कई तरीकों से याचिका में संशोधन की मांग की गई। इसका आधार यह था कि पुरानी सीपीसी को लगभग 22.06.2002 को संशोधित किया गया था, जो 01.07.2002 से लागू हुआ, इसलिए वादियों ने याचिका में कई संशोधनों की प्रार्थना की।

6. प्रतिवादियों ने आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के तहत वादी द्वारा दायर याचिका पर 06.07.2022 पर प्रत्युत्तर भी दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त याचिका अवैध है, बनाए रखने योग्य नहीं है और खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

7. जब मुकदमा दायर किया गया, वादियों को यह जानकारी थी कि ज़मीबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण संख्या 46/1996 में, उत्तर छोटानागपुर विभाग, हजारीबाग के आयुक्त की अदालत ने 16.08.1999 को आदेश पारित किया और अतिरिक्त कलेक्टर, गिरिडीह की अदालत के आदेश को रद्द कर दिया, जबकि वादियों ने उक्त विवादित आदेश को चुनौती नहीं दी। मामला अंतिम चरण में है और यदि इस प्रकार के समयसीमा से बाधित संशोधनों की अनुमति दी जाती है, तो यह मामले को पुनः खोलने के समान होगा और मुकदमे की नई सुनवाई शुरू होगी, जिससे मुकदमे की प्रकृति और चरित्र बदल जाएगा। इसलिए, प्रतिवादियों ने वादियों द्वारा 13.02.2020 को दायर संशोधन याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान शीर्षक मुकदमा संख्या 167/1999 में दोनों पक्षों के गवाहों का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है और मामला अंतिम निर्णय पारित करने के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, इस चरण में याचिका में संशोधन पूरी तरह से अनुचित और अवैध है।

8 विद्वान अतिरिक्त मुन्सिफ-XX, गिरिडीह ने, पक्षों की सुनवाई के बाद, हालांकि, 26.04.2023 को एक आदेश पारित किया है, जिसमें वादियों द्वारा 13.02.2020 को दायर याचिका को आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत अनुमति दी गई है। इसमें कहा गया है कि वादी को याचिका के पैरा 18, 19 और 23 में संशोधन करने के लिए निर्देशित किया गया है और पैरा 18 के बाद मांगी गई घोषणा जोड़ने के लिए कहा गया है, तथा पैरा 19 के बाद पैरा 19(1) और नए बनाए गए पैरा 19(1) के बाद पैरा 19(2) जोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, याचिका में मांगे गए संशोधन के अनुसार पैरा 23 में पैरा 23(a)(i) जोड़ने का निर्देश दिया गया है, जिसे इस आदेश के 7 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। इसलिए, वर्तमान याचिका पर विचार किया जा

रहा है।

9. यह याचिका के बयानों से स्पष्ट होता है कि मुकदमा दायर करते समय कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई थी। इस प्रकार, सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से याचिका में किए गए बयानों में संशोधन की अनुमति मांगी गई है।

10. सी.पी.सी. के आदेश VI नियम 17 के तहत दायर याचिका से यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित संशोधन की मांग की गई है जो निम्नानुसार हैः

"i) विद्वान न्यायालय वादी को संशोधन संख्या 46/1996 और पूर्ण विराम के बाद, वाद के पैरा संख्या18 के अंत के बाद निम्नलिखित बयान लिखने की अनुमति दे सकता हैः-

वादियों का अधिकार, शीर्षक, हित और मुकदमे की भूमि पर कब्जा मौजूद है और जारी है, और इसे हजारीबाग के आयुक्त के आदेशों के संदर्भ में समाप्त नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादियों ने आयुक्त के आदेशों के संदर्भ में मुकदमे की भूमि पर कोई अधिकार, शीर्षक, हित और कब्जा अर्जित नहीं किया। राजस्व अधिकारियों के आदेश नागरिक न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं हैं। नागरिक न्यायालय का निर्णय राजस्व अदालत पर बाध्यकारी है।

(ii) विद्वत न्यायालय वादी को वाद के पैरा no.19 के अंत के बाद एक नया अनुच्छेद संख्या19 (1) बनाने की अनुमति दे सकता है, और वादी को पूर्ववत दस्तावेज़ और पूर्ण विराम के बाद निम्नलिखित बयान लिखने की अनुमति दे सकता हैः-

अभियुक्त और दाता, श्रीमती आयन कुमारी, या कोई अन्य व्यक्ति कभी भी मुकदमे की भूमि, जो 9.65 एकड़ है, का मालिक नहीं था और किसी ने भी इस मुकदमे में शामिल भूमि के उक्त क्षेत्र को भूदान यज्ञ समिति या आचार्य विनोबा भावे के पक्ष में दान नहीं किया। तथाकथित दाता, श्रीमती आयन कुमारी, ने कभी भी उक्त दान के संबंध में किसी भी समय कोई लिखित घोषणा नहीं की। भूमि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में गैर-मजूरी भूमि के रूप में दर्ज है, जिसका एक भाग खास है जबकि दूसरा भाग आम भूमि है, और किसी ने भी मुकदमे की भूमि के संबंध में भूदान यज्ञ समिति के पक्ष में कोई दान पत्र जारी और सौंपा नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। 9.65 एकड़ क्षेत्र की भूमि का निपटान अहलि मियाँ और सिज़मान मियाँ के पुत्रों के पक्ष में भूदान पत्र के माध्यम से नहीं किया गया, जो कथित रूप से वर्ष 1956 में दिया गया था।

(iii) विद्वत न्यायालय वादी को नए बनाए गए पैरा संख्या19 (1) के अंत के बाद अनुच्छेद संख्या19 (2) बनाने की अनुमति दे सकता है और वादी को निम्नलिखित बयान लिखने की अनुमति दे सकता हैः –

कोई राजस्व अधिकारी निर्धारित तरीके से कोई प्रकाशन नहीं किया था, जिसमें प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर लिखित आपत्ति आमंत्रित की गई हो। किसी भी सक्षम प्राधिकरण द्वारा उक्त दानकर्ता के अधिकार, शीर्षक और क्षमता के संबंध में कोई जांच नहीं की गई, यदि कोई हो, जो उक्त दान पत्र बनाने के लिए आवश्यक थी। इसे कभी भी किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा पुष्टि नहीं की गई। मुकदमे की भूमि कभी भी भूदान यज्ञ समिति को स्थानांतरित और संपन्न नहीं की गई। संबंधित अवधि के दौरान प्रतिवादियों में से कोई भी भूमिहीन व्यक्ति नहीं था।

iv) माननीय अदालत वादियों को नये राहत संख्या ए (i) में पैरा संख्या 23 में निम्नलिखित बयान लिखने की अनुमति देने में प्रसन्नता महसूस कर सकता है|

न्यायनिर्णयन पर, यह अभिनिर्धारित करते हुए आदेश पारित किया जाए कि प्रतिवादियों के पूर्वजों के पक्ष में कथित भूदान समझौता और कथित भूदान पत्र जारी करना अवैध, शून्य, निष्क्रिय है और यह वादी पर बाध्यकारी नहीं है।"

11. उक्त याचिका के प्रति एक प्रत्युत्तर दायर किया गया है, जिसमें गंभीर आपत्ति उठाई गई है कि उक्त संशोधन को इतनी लंबी देरी के बाद अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, खासकर जब मामला बहस के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिका में किए जाने वाले संशोधन का संदर्भ लेते हुए, जिसे आदेश VI नियम 17 के तहत दायर किया गया है, माननीय अदालत ने यह विचार नहीं किया कि मुकदमे की प्रकृति ही बदल जाएगी।

12. माननीय अदालत ने, पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों की विवेचना करते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि पक्षों के बीच वास्तविक विवाद को निर्धारित करने के लिए, निर्णय के उद्घोषण से पहले भी संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, और आगे यह विचार करते हुए कि किया जाने वाला संशोधन विवाद के वास्तविक निपटान के लिए है, इस प्रकार, सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत दायर याचिका को 26.04.2023 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई है, जिसे वर्तमान याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए चुनौती दी गई है, अर्थात् इसके पर्यवेक्षणीय अधिकार क्षेत्र के तहत।

13. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता श्री पी.के. मुखोपाध्याय, सहायक श्री एस.के.मूर्ति के साथ, ने प्रस्तुत किया कि माननीय अदालत ने सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत दायर याचिका को अनुमति देकर गंभीर त्रुटि की है, यह कहते हुए कि याचिका में संशोधन की अनुमति देने की स्थिति में, यह स्पष्ट है कि यह बहुत लंबे समय के बाद किया जा रहा है और यह भी कि मामला बहस के लिए निर्धारित किया गया है।

14. इसके अलावा, इस तरह के संशोधन की अनुमति देने के लिए उपयुक्त नहीं है यदि मुकदमे की प्रकृति को बदला जा रहा है, लेकिन उपरोक्त कानूनी स्थिति की विवेचना किए बिना, विवादित आदेश पारित किया गया है, जैसे कि तत्काल याचिका।

15. दूसरी ओर, श्री भैया विश्वजीत कुमार, वादियोंप्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता/, जो मुकदमे के वादी हैं, ने विवादित आदेश का बचाव करते हुए कहा कि मांगा गया संशोधन मुकदमे की प्रकृति को बदलने वाला नहीं कहा जा सकता।

16. इसके अलावा, विवाद को सुलझाने के लिए मूल मुद्दा यह है कि प्रतिवादी, याचिकाकर्ता, जो संपत्ति पर अधिकार और शीर्षक का दावा कर रहा है, वह भूमि के निपटान के लिए दान पत्र के आधार पर है, जिसे श्रीमती आयन कुमारी द्वारा दान किए जाने का दावा किया गया है। इसे शामिल करने की मांग की गई है, क्योंकि वादियों के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार कोई दान पत्र नहीं है।

17. वादियोंप्रतिवादियों के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय अदालत ने - यह सुनिश्चित किया है कि संशोधन को वास्तविक विवाद को सुलझाने के लिए निर्णय के उद्घोषण से पहले भी अनुमति दी जा सकती है, ताकि विवाद को भविष्य में सभी समय के लिए उपलब्ध आधारों और मुद्दों के साथ सुलझाया जा सके।

18. विद्वान अधिवक्ता ने, उपरोक्त आधार के आधार पर, प्रस्तुत किया है कि विवादित आदेश को त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

19. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, विवादित आदेश में विद्वान न्यायालय द्वारा दर्ज अभिवचनों और निष्कर्षों पर गौर किया है।

20. यह न्यायालय, विवादित आदेश की वैधता और औचित्य में प्रवेश करने से पहले, सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान को संदर्भित करना उचित और उचित समझता है जो निम्नानुसार है:

> *"17. बयानों में संशोधन:- न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर किसी भी पक्ष को अपनी दलीलों को इस तरह से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है जो न्यायसंगत हों, और सभी ऐसे संशोधन उन उद्देश्यों के लिए किए जाएंगे जो पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के कारण को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं: शर्त यह है कि परीक्षण शुरू होने के बाद कोई संशोधन के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्ष ने परीक्षण की शुरुआत से पहले इस मामले को नहीं उठाया।"*

21. यह स्पष्ट है कि उपरोक्त संदर्भित प्रावधान का उद्देश्य वास्तविक न्याय करना है और यदि कुछ चीजें या दस्तावेज़ याचिका या लिखित बयान में रिकॉर्ड पर नहीं लाए जा सके, तो उन्हें संबंधित निचली अदालत से अनुमति मांगकर आदेश VI नियम 17 के तहत याचिका दायर करके रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है।

22. कानून की स्थिति के संदर्भ में, संशोधन की अनुमति देने या उसे अस्वीकार करने के संबंध में, यह स्पष्ट है कि यह कानून अच्छी तरह से स्थापित है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजकुमार गुरवारा बनाम एससरवागी और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और .के. अन्य के मामले में **)2008) 14** एससीसी **364** में कहा है, जिसमें पैरा-18 में निम्नलिखित बात रखी गई है:

> *"18. आगे यह बताना प्रासंगिक है कि मूल मुकदमे में, वादी ने खनन संचालन करने और मुकदमे की अनुसूची की संपत्ति का उपयोग और बिक्री करने के अपने विशेष अधिकार की घोषणा की मांग की थी, और तर्कों के दौरान दायर याचिका में, उसने दूसरे प्रतिवादी से कब्जा और हर्जाना वसूलने की प्रार्थना की। यह स्थापित कानून है कि संशोधन के लिए आवेदन की स्वीकृति कुछ शर्तों के अधीन होती है, अर्थात्) :i) जब इसकी प्रकृति को संशोधन की अनुमति देकर बदला जाता है; (ii) जब संशोधन नए कारण का परिचय देता है और दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है; (iii) जब संशोधन आवेदन की अनुमति देने से समय सीमा के कानून का उल्लंघन होता है। वादी न केवल आदेश 6 नियम 17 के उपबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहा, बल्कि merits पर भी उसका दावा अस्वीकार किए जाने योग्य है। सभी संबंधित पहलुओं पर उच्च न्यायालय ने उचित रूप से विचार किया और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के 10-03-2004 के आदेश को सही तरीके से रद्द कर दिया।"*

23. इसी दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "रेवाजीतू बिल्डर्स और डेवलपर्स बनाम नारायणस्वामी एंड संस और अन्य" (2009) 10 एससीसी 84 में दिए गए निर्णय में दोहराया गया है। प्रासंगिक पैरा-63 इस प्रकार है:

> *"63. अंग्रेजी और भारतीय दोनों मामलों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने पर, कुछ बुनियादी सिद्धांत सामने आते हैं जिन्हें संशोधन के लिए*

आवेदन को अनुमति देते या अस्वीकार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिएः

(1) क्या मांगा गया संशोधन मामले के उचित और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक है?

(2) संशोधन के लिए आवेदन प्रामाणिक है या दुर्भावनापूर्ण;

(3) संशोधन से दूसरे पक्ष के लिए ऐसा पूर्वाग्रह पैदा नहीं होना चाहिए जिसे धन के संदर्भ में पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है;

(4) संशोधन से इनकार करने से वास्तव में अन्याय होगा या कई मुकदमेबाजी होगी।

(5) क्या प्रस्तावित संशोधन संवैधानिक रूप से या मौलिक रूप से मामले की प्रकृति और चरित्र को बदल देता है; और

(6) सामान्य नियम के रूप में, यदि संशोधित दावों पर नया मुकदमा आवेदन की तिथि पर समय सीमा के कारण बाधित होगा, तो अदालत को संशोधनों को अस्वीकार करना चाहिए।

ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें आदेश 6 नियम 17 के तहत दायर आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। ये केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

24. उपरोक्त निर्णय से यह प्रतीत होता है कि संशोधन वाद में या लिखित कथन में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त है, सिवाय इसके कि यदि वाद की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होने जा रहा है।

25. इसके अलावा, यदि कोई ऐसा संशोधन अनुमति के योग्य नहीं है, और यदि मुकदमा दायर करने के बाद कोई राहत मांगी जा रही है, जो समय सीमा के कारण बाधित है और उक्त मुद्दे के खिलाफ है, यदि मुकदमा समय सीमा के आधार पर दायर नहीं किया जा सकता, तो ऐसी राहत याचिका में संशोधन मांगकर नहीं मांगी जा सकती। आगे, सिद्धांत यह है कि एक बार जब बयानों या लिखित बयान में स्वीकार्यता हो जाती है, तो उक्त बयान को संशोधन याचिका दायर करके वापस नहीं लिया जा सकता, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "अशुतोष चतुर्वेदी बनाम प्राणो देवी @ परानी देवी और अन्यके मामले में कहा है ", जो)**2008) 15** एससीसी **610** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें पैरा-16 में निम्नलिखित कहा गया है:

"16. टी.एन. एलाय फाउंड्री को. लिमिटेड बनाम टी.एन. विद्युत् बोर्ड [(2004) 3 एससीसी 392] में, इस अदालत ने एल.जे. लीच एंड को. लिमिटेड बनाम जार्डाइन स्किनर एंड को. [ए.आइ.आर 1957 SC 357 : 1957 एससीआर 438] में अपने पूर्व निर्णयों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि सामान्यतः, अदालत संशोधन की अनुमति देने से इंकार करेगी यदि संशोधित दावे पर नया मुकदमा आवेदन की तिथि पर समय सीमा के कारण बाधित हो गया हो। (इसके अलावा, राज्य बैंक ऑफ हैदराबाद बनाम टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल [(2007) 1 एससीसी 765 : (2006) 13 स्केल 332] देखें।)"

26. इसी तरह, रेवाजीतू बिल्डर्स और डेवलपर्स बनाम नारायणस्वामी एंड संस और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, (ऊपर), जिसमें, पैराग्राफ-39 में अभिनिर्धारित किया, निम्नानुसार है:

> *"39. हालांकि, यह नियम सार्वभौमिक नहीं है और कुछ परिस्थितियों में, अदालत परिसीमा के कानून के बावजूद ऐसे संशोधन की अनुमति दे सकती है। तथ्य यह है कि दावा परिसीमा के कानून द्वारा बाधित है, अदालत द्वारा संशोधन की अनुमति या अस्वीकृति के संबंध में विवेक का प्रयोग करते समय ध्यान में रखने वाले कारकों में से एक है, लेकिन यदि न्याय के हित में संशोधन की आवश्यकता है, तो यह अदालत की शक्ति को प्रभावित नहीं करता (देखें गंगा बाई बनाम विजय कुमार [(1974) 2 एससीसी 393] और अरुंधति मिश्रा बनाम राम चरित्र पांडे [(1994) 2 एससीसी 29])।"*

27. यह भी स्थापित है कि संशोधन किसी भी समय मुकदमे में अनुमति दी जा सकती है या यहां तक कि इसे देर से भी अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "सुरेंद्र कुमार शर्मा बनाम माखन सिंहके मामले में दिए गए निर्णय का " संदर्भ लिया जा सकता है, जो **)2009) 10** एससीसी **626** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें पैरा-5 में निम्नलिखित कहा गया है:

> *"5. जैसा कि पहले यहां उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने संशोधन की प्रार्थना को दो कारणों से अस्वीकार किया। पहले कारण के संबंध में, अर्थात् संशोधन की प्रार्थना देर से की गई थी, हमारा मानना है कि भले ही यह देर से की गई हो, फिर भी यह देखना आवश्यक है कि क्या संशोधन की अनुमति देने से पक्षों के बीच वास्तविक विवाद का समाधान किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत, अदालत को पक्ष को बयानों में संशोधन की अनुमति देने के लिए व्यापक शक्तियाँ और बिना किसी प्रतिबंध का विवेक दिया गया है, जिस प्रकार से अदालत को उचित और सही प्रतीत होता है। भले ही, याचिका में संशोधन के लिए आवेदन देर से दायर किया गया हो, यदि यह पाया जाता है कि पक्षों के बीच वास्तविक विवाद को सुलझाने के लिए इसे लागत चुकाने पर अनुमति दी जा सकती है, तो ऐसी देर से की गई संशोधन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, हमारे विचार में, संशोधन के लिए आवेदन करने में केवल देरी और लाचारी संशोधन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती।"*

28. इसी तरह, "माउंट मैरी एंटरप्राइजेज बनाम जीवरत्ना मेडिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड" के मामले में, जो (2015) 4 एससीसी 182 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-7 और 10 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

> *"7. हमारी राय में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार, संशोधन आवेदन को सामान्य रूप से तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि संशोधन के कारण वाद की*

प्रकृति में परिवर्तन न हो जाए या प्रतिवादी को कोई पूर्वाग्रह न हो। वर्तमान मामले में, संशोधन आवेदन स्वीकार करने के कारण वाद की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाना था क्योंकि वाद विशिष्ट प्रदर्शन के लिए था और आरंभ में संपत्ति का मूल्यांकन 13,50,000 रुपये किया गया था, लेकिन चूंकि संपत्ति का बाजार मूल्य वास्तव में 1,20,00,000 रुपये था, इसलिए अपीलकर्ता-वादी ने संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था ताकि वाद में वाद की संपत्ति का सही मूल्य दिया जा सके।

***10**. वाद के संशोधन के संबंध में, इस न्यायालय द्वारा उत्तर पूर्वी रेलवे प्रशासन नाम भगवान दास [(2008) 8 एस. सी. सी. 511]: (एस. सी. सी. पृष्ठ 517, पैरा 16) में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:*

"16. जहां तक आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. (जैसा कि प्रासंगिक समय में था) के तहत संशोधनों को मंजूरी देने या न देने के प्रश्न को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का संबंध है, ये भी अच्छी तरह से स्थापित हैं। आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. कार्यवाही के किसी भी चरण में दलीलों में संशोधन की परिकल्पना करता है। पीरगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम कलगोंडा शिदगोंडा पाटिल [ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 363: (1957) 1 एस.सी.आर. 595] में, जो अभी भी मान्य है, यह माना गया था कि सभी संशोधनों को अनुमति दी जानी चाहिए जो दो शर्तों को पूरा करते हैं: (ए) दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं करना, और (बी) पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक होना। संशोधनों को केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जब दूसरे पक्ष को उसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता है जैसे कि दलील मूल रूप से सही थी, लेकिन संशोधन से उसे ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई लागतों से नहीं की जा सकती।"

29. इसके अलावा, सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर यह है कि संबंधित अदालत को अनुमति देते समय यह देखना होगा कि संशोधन की अनुमति देकर मुकदमे की प्रकृति को बदलने की अनुमति नहीं दी गई है।

30. यह न्यायालय अब उपरोक्त कानूनी स्थिति के आधार पर तथ्यात्मक पहलू की जांच करने जा रहा है।

31. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्क और दलील के अनुसार यहां स्वीकार किया गया मामला यह है कि वादीगण, जो यहां प्रतिवादी हैं, द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अधिकार और स्वामित्व की घोषणा के लिए एक शीर्षक वाद दायर किया गया है, हालांकि, यह वाद वर्ष 1999 का है।

32. यह भी स्वीकार किया गया है कि मुकदमा आगे बढ़ चुका है और अब यह तर्क के चरण में है जैसा कि पक्षों की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त चरण में, सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत एक याचिका दायर की गई है जिसमें संशोधन की मांग की गई है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

33. यह स्पष्ट है कि सम्मिलित किया जाने वाला पहला संशोधन, शिकायत के पैरा संख्या 18 के अंत के बाद संशोधन संख्या 46/1996 और पूर्ण विराम के पश्चात निम्नलिखित कथन को

सम्मिलित करना है:

"वादी पक्ष का अधिकार, शीर्षक, हित और कब्जा मुकदमे की भूमि पर मौजूद है और जारी है और इसे आयुक्त, हजारीबाग के आदेशों के मद्देनजर नहीं खोया जा सकता है। प्रतिवादियों ने आयुक्त के आदेशों के मद्देनजर मुकदमे की भूमि पर कोई अधिकार, शीर्षक, हित और कब्जा अर्जित नहीं किया है। राजस्व अधिकारियों के आदेश विद्वान सिविल न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं हैं। सिविल न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी है।"

34. शिकायत के पैरा 19 के अंत के बाद एक नया पैरा 19(1) बनाने के लिए आगे संशोधन की मांग की गई है, और वादी को पूर्व-दिनांकित दस्तावेज़ और पूर्ण विराम के बाद निम्नलिखित कथन लिखने की अनुमति दी गई है:

"संदिग्ध और तथाकथित दाता श्रीमती आयन कुमारी या कोई अन्य व्यक्ति कभी भी मुकदमे के भूखंड में 9.65 एकड़ भूमि का मालिक नहीं था और किसी ने भी इस मुकदमे में शामिल भूखंड के उक्त क्षेत्र को भूदान यज्ञ समिति या आचार्य विनोबा भावे के पक्ष में दान नहीं किया। संदिग्ध दाता श्रीमती आयन कुमारी ने कभी भी उक्त संदिग्ध दान के लिए किसी भी समय लिखित घोषणा नहीं की। भूमि को अधिकारों के अभिलेख में गैरमजूरिया भूमि के रूप में दर्ज किया गया - है, जिसका एक भाग खास है जबकि दूसरा आम भूमि है, और किसी ने भी भूदान यज्ञ समिति के पक्ष में मुकदमे की भूमि के संबंध में कोई दान पत्र जारी और सौंपा नहीं। 9.65 एकड़ भूमि का निपटान कभी भी अहदिल मियाँ और सिज़मान मियाँ के पुत्रों के पक्ष में भूदान पर्चा द्वारा नहीं किया गया, जो कथित रूप से वर्ष 1956 में 9.65 एकड़ के लिए दिया गया था।"

35. इसके अलावा, नव निर्मित पैरा संख्या 19(1) के अंत के बाद, निम्नलिखित प्रभाव से नया पैरा संख्या 19(2) जोड़ने की अनुमति मांगने के लिए संशोधन मांगा गया है:

"किसी भी राजस्व अधिकारी ने प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर लिखित आपत्ति आमंत्रित करते हुए निर्धारित तरीके से कोई प्रकाशन नहीं किया था। कथित दानदाता के अधिकार, शीर्षक और कथित दान पत्र बनाने की योग्यता के बारे में किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी। किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। मुकदमे की भूमि कभी भी भूदान यज्ञ समिति को हस्तांतरित और निहित नहीं की गई थी। प्रासंगिक अवधि के दौरान कोई भी प्रतिवादी भूमिहीन व्यक्ति नहीं था।"

36. इसके अलावा, शिकायत के पैरा संख्या 23 में एक नई राहत संख्या ए(i) जोड़ने के लिए संशोधन की मांग की गई है, जो इस प्रकार है:

"न्यायिक निर्णय पर, यह निर्णय पारित किया जाए कि कथित भूदान समझौता और प्रतिवादियों के पूर्वजों के पक्ष में कथित और कथित भूदान पर्चों का जारी किया जाना अवैध, शून्य, अमान्य, अशक्त, आरंभ से ही अमान्य, निष्क्रिय है और यह वादी पर बाध्यकारी नहीं है।"

37. पहला संशोधन इस संदर्भ के आधार पर है, अर्थात वादी का अधिकार, शीर्षक और हित तथा वाद भूमि पर कब्जा विद्यमान है और जारी है तथा आयुक्त, हजारीबाग के आदेशों के मद्देनजर इसे समाप्त नहीं कहा जा सकता।

38. आगे यह तर्क दिया गया है कि केवल इसलिए कि आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया गया है, प्रतिवादी संबंधित भूमि पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते।

39. इस न्यायालय के अनुसार, ऐसा संशोधन इस विधिक स्थिति पर आधारित है कि राजस्व प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को अधिकार और स्वामित्व की घोषणा का आधार नहीं कहा जा सकता। यद्यपि, राजस्व प्राधिकरण द्वारा पारित ऐसे आदेश को केवल अधिकार और स्वामित्व के विचार के लिए साक्ष्य माना जा सकता है। इसलिए, जब ऐसा कथन केवल यह कथन देने के लिए किया जा रहा है कि केवल इसलिए कि आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया गया है, वह प्रश्नगत संपत्ति पर याचिकाकर्ता के अधिकार, स्वामित्व, हित और कब्जे को नहीं छीन सकता है, तो इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, वाद के पैरा संख्या 18 के अंत के बाद उक्त कथन को सम्मिलित करने के लिए विद्वान परीक्षण न्यायालय की अनुमति मांगना, मुकदमे की प्रकृति को बदलने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे कानून की स्थापित स्थिति पर आधारित कहा जाएगा।

40. दूसरी और तीसरी संशोधन उस शीर्षक पर आधारित है, जिसे प्रतिवादी ने दावा किया है, जो यहां याचिकाकर्ता है, भूमि के निपटान के आधार पर। यह बयान दिया गया है कि भूमि, जो स्पष्ट रूप से गैरमजूरिया आम है। निपटान का -मजूरिया का हिस्सा है और एक भाग गैर-दावा उक्त भूमि पर आधारित है, जो भूदान यज्ञ अधिनियम के तहत दान की गई थी।

41. उक्त अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधान यह है कि यदि भूमि भूदान यज्ञ अधिनियम के तहत दान की गई है, तो इसे नई गठित समिति के पक्ष में दान किया जाना चाहिए। समिति को दान पत्र जारी करने की आवश्यकता है और उसके बाद ही अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से, भूमि का निपटान सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

42. यह न्यायालय, अनुच्छेद-19(1) और 19(2) के तहत प्रस्तावित संशोधन को देखकर यह विचार करता है कि यह भी कानूनी स्थिति पर आधारित है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त संशोधन को शामिल करने से मुकदमे की प्रकृति में परिवर्तन होगा, क्योंकि यह कानूनी सिद्धांत पर आधारित है।

43. यह न्यायालय, उपरोक्त तथ्य पर चर्चा करने के बाद और विवादित आदेश पर वापस आते हुए, यह विचार करता है कि अधिवक्ता न्यायालय ने इस मुद्दे के मूल को ध्यान में रखते हुए इन दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर विचार किया है और यह स्थापित स्थिति को ध्यान में रखा है कि यदि दस्तावेज या बयान वास्तविक विवाद के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए।

44. यह न्यायालय, वहां दिए गए निष्कर्ष के आधार पर, यह विचार करता है कि उपरोक्त संदर्भित तर्क पर आधारित उक्त निष्कर्ष को त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता।

45. यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के प्रावधान के तहत दायर की गई है और यह कानून की स्थापित स्थिति है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की सीमित न्यायिक शक्ति होती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शालिनी श्याम शेट्टी बनाम राजेंद्र शंकर पाटी के मामले में कहा है, जो **(2010) 8** एससीसी **329** में रिपोर्ट किया गया है। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 227 के दायरे के बारे में बताया है, जो उच्च न्यायालयों की पर्यवेक्षी शक्तियों से संबंधित है और

कोलकाता उच्च न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ द्वारा डालमिआ जैन एयरवेज़ लिमिटेड बनाम सुकुमार मुखर्जी के मामले में दिए गए निर्णय का सहारा लिया गया है, जो ए.आइ.आर **1951** कोलकाता **193** में रिपोर्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को असीमित शक्ति नहीं देता है जिसे विशेष निर्णयों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अदालत की इच्छा से प्रयोग किया जा सके। पर्यवेक्षण का अधिकार एक ज्ञात और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त चरित्र की शक्ति प्रदान करता है और इसे उन न्यायिक सिद्धांतों पर लागू किया जाना चाहिए जो इसे उसका चरित्र देते हैं। सामान्य शब्दों में, उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अधीनस्थ अदालतों को उनके अधिकारों की सीमाओं के भीतर बनाए रखने के लिए होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और इसे कानूनी तरीके से करें।

i. पर्यवेक्षण की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वहाँ कुछ नहीं हुआ हो;
(क) अधिकारिता की अनुचित धारणा, जो किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में निहित नहीं है; या
(ख) अधिकारिता का घोर दुरुपयोग; या
(ग) न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने से अनुचित इनकार

ii. इसके अलावा, उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मणि नरिमन दारूवाला बनाम फिरोज एनभटेन . के मामले में दिए गए निर्णय का सहारा लिया है, जो **1991) 3** एससीसी **141** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय केवल उस स्थिति में एक अधीनस्थ अदालत या न्यायाधिकरण के निर्णय को रद्द या पलट सकता है जहाँ कोई साक्ष्य नहीं है या जहाँ कोई भी समझदार व्यक्ति उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता जो अदालत या न्यायाधिकरण ने निकाला है।

iii. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस सीमित सीमा को छोड़कर उच्च न्यायालय के पास तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

iv. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लक्ष्मीकांत रेवचंद भोजवानी बनाम प्रतापसिंह मोहनसिंह पर्देशी के मामले में दिए गए निर्णय में, जो **)1995) 6** एससीसी **576** में रिपोर्ट किया गया है, कहा गया है कि अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय सभी प्रकार की कठिनाइयों या गलत निर्णयों को सुधारने के लिए असीमित विशेषाधिकार नहीं ले सकता। इसका प्रयोग गंभीर कर्तव्य की लापरवाही और कानून एवं न्याय के मौलिक सिद्धांतों के स्पष्ट दुरुपयोग तक सीमित होना चाहिए।

v. उपरोक्त निर्णय के पैरा 47 में कहा गया है कि अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र न तो मूल है और न ही अपील योग्य। अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षण का यह अधिकार दोनों प्रशासनिक और न्यायिक पर्यवेक्षण के लिए है। इसलिए, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ अलग और विशिष्ट हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। इन दोनों अधिकार क्षेत्रों के बीच एक और अंतर यह है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सामान्यतः एक आदेश या कार्यवाही को रद्द या निरस्त करता है, लेकिन अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय, कार्यवाही को निरस्त करने के अलावा, विवादित आदेश को उस आदेश से प्रतिस्थापित भी कर सकता है जो अधीनस्थ न्यायाधिकरण को बनाना चाहिए था।

vi. इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की

जाने वाली शक्तियों के बारे में कहा गया है। उच्च न्यायालय, अपने पर्यवेक्षण के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, केवल इस उद्देश्य से आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है कि अधीनस्थ न्यायाधिकरण और अदालतें अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर रहें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे न्यायाधिकरण और अदालतें अपने पास निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें और अपने पास निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना न करें। इसके अलावा, उच्च न्यायालय तब अपने पर्यवेक्षण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है जब अधीनस्थ न्यायाधिकरण और अदालतों के आदेशों में स्पष्ट विकृति हो या जहाँ न्याय का गंभीर और स्पष्ट उल्लंघन हुआ हो या प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो।

vii. अपने पर्यवेक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय केवल कानून या तथ्य की साधारण गलतियों को सुधारने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या इसलिए कि अधीनस्थ न्यायाधिकरण या अदालतों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण के अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण संभव है। दूसरे शब्दों में, इसका अधिकार क्षेत्र बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए।

46. यह न्यायालय, ऊपर की गई चर्चा और ऊपर उल्लिखित कानूनी स्थिति के आधार पर, इस विचार पर है कि विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

47. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका असफल होती है और इसे अस्वीकृत किया जाता है।

48. चूंकि, विद्वान न्यायालय ने प्रतिवादी, याचिकाकर्ता को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, इसलिए इस संबंध में आगे कोई टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायधीश)

रोहित/एएफआर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|